



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 फाल्गुन 1934 (श0)
(सं0 पटना 181) पटना, मंगलवार, 5 मार्च 2013

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना
4 फरवरी 2013

सं0 22/नि0सि0(वीर0)—07—12/2004/146—श्री संजीवन चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध उनके तिरहुत नहर अंचल, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन अधीन वर्ष 2006—07 के दौरान दिनांक 7.1.07 को तिरहुत नहर मुख्य नहर के वि0दू0—65.00 बायों पर टूटान एवं उसी स्थल पर दिनांक 13.1.07 को नहर में हुए टूटान के संबंध में योजना एवं मोनेटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए उनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय संकल्प सह ज्ञाप सं0—444 दिनांक 11.3.10 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

उक्त विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के पूर्व श्री चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता के दिनांक 31.5.11 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप श्री चौधरी के विरुद्ध सेवाकाल में नियम 17 के तहत प्रारम्भ की गयी विभागीय कार्यवाही को विभागीय अधिसूचना 677 दिनांक 10.6.11 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 के तहत सम्परिवर्तित की गयी।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 381 दिनांक 12.4.12 द्वारा सरकारी कार्य के निष्पादन में बरती गयी शिथिलता एवं दायित्वों के निर्वहन में बरती गयी अनियमितता से सरकार को हुई वित्तीय क्षति के लिए श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया। श्री चौधरी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जबाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त निम्नलिखित आरोपोंको उनके विरुद्ध प्रमाणित पाये गये:—

(1) श्री चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में विभागीय पत्रांक 1256 दिनांक 23.12.06 का इनके द्वारा पूणतः पालन किया गया बताया गया है। वस्तुतः यह पत्र दिनांक 31.12.06 का है। इस कथन के समर्थन में श्री चौधरी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि श्री चौधरी द्वारा विभागीय पत्रांक 1256 दिनांक 30.12.06 में निहित अनुदेशों का पालन किया गया होता तो दिनांक 7.1.07 को हुए टूटान की सूचना दिनांक 11.1.07 एवं दिनांक 13.1.07 को हुए टूटान की सूचना दिनांक 19.1.07 को मुख्य अभियन्ता को न देकर टूटान के ही दिन दी गयी होती चूँकि उक्त पत्र में अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नहरों का प्रतिदिन निरीक्षण कर प्रतिवेदन देने का उल्लेख है। अतएव श्री चौधरी तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता के स्तर पर नहर पर्यवेक्षण में कमी पाया गया है।

आरोप सं०-2 के संबंध में श्री चौधरी द्वारा अपने उत्तर में टूटान की मरम्मत का कार्य दूसरे सहायक अभियन्ता से कराने का आदेश देने में मुख्य अभियन्ता से थोड़ा विलम्ब होने की बात कही गयी है जबकि नहर टूटान की मरम्मत का कार्य असम्बद्ध प्रमण्डल द्वारा कराये जाने के विभागीय निदेश की अवहेलना करते हुए श्री चौधरी के पत्रांक 65 दिनांक 10.1.07 द्वारा मरम्मत का कार्य विभागीय रूप से कराने का प्रस्ताव दिया गया था। अतएव इनके द्वारा अनियमित ढंग से नहर टूटान की मरम्मत कराने के प्रस्ताव से विभागीय पत्रांक 1295 दिनांक 25.8.90 में निहित निदेशों की अवहेलना का आरोप भी उनके विरुद्ध प्रमाणित होता है।

आरोप सं०-3 के संबंध में श्री चौधरी का यह कथन कि नहर संचालन में स्थानीय लोगों के गलत हस्तक्षेप से पानी को अनियंत्रित कर नुकसान पहुंचाया जाता है एवं ऐसी स्थिति सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है ग्राह्य नहीं होता है। उल्लेखित परिस्थिति में असमाजिक तत्वों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए थी, जो श्री चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नहीं किया गया। श्री चौधरी, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नहर का संचालन गंभीरतापूर्वक नहीं लिया गया जबकि विभागीय पत्रांक 1256 दिनांक 30.12.06 की कड़िका-11 के अनुसार नहरों में प्रवाहित जलश्राव का गहन प्रबोधन अधीक्षण अभियन्ता स्तर पर किया जाना चाहिए था जिसका अनुपालन श्री चौधरी द्वारा नहीं किये जाने के कारण ही मरम्मत के पश्चात पुनः उसी स्थल पर टूटान हुआ जिससे विभाग को वित्तीय क्षति हुई।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार के स्तर पर समीक्षोपरान्त श्री चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है।

1. "पांच प्रतिशत पेंशन पर सदा के लिए रोक"

उक्त दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1949 दिनांक 6.12.12 द्वारा सहमति प्राप्त है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री संजीवन चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, तिरहुत नहर अंचल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी० के तहत निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है:-

"पांच प्रतिशत पेंशन पर सदा के लिए रोक"

उक्त आदेश श्री चौधरी को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 181-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>